रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 27 जून, 1989/6 आषाढ़, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 1989

क्रमांक एल0एल0आर0 (डी0) (6)-2/89-लैजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 23 जून, 1989 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1989 (1989 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 1989 के

हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन, इसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में सहर्ष प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव ।

1989 का अधिनियम संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1989

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23 जून, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1989 है ।

धारा 163 का संशोधन ।

1954 का 6

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 163 में--

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में आए "five hundred" और "one thousand" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "one thousand" और "two thousand" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (5) और उप-धारा (6) जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:--

"(3) When there is a question as to title or to the adverse possession, wherein the possession is claimed by an encroacher for a period beyond thirty years in relation to the land from which ejectment is made or is to be made under this section, the Revenue Officer, not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade, shall proceed to determine the question, as if he were a civil court and shall exercise all such powers as are exerciseable by a civil court.

(4) For the determination of the question under sub-section (3), the Revenue Officer shall follow the same procedure as is applicable to the trial of an original suit by a civil court, and he shall record a judgement and decree containing the particulars required by the Code of Civil Procedure, 1908 to be specified therein.

1908 का 5

(5) An appeal from the decree of the Revenue Officer made under sub-section (4) shall lie to the District Judge as if that decree were a decree of a Subordinate Judge in an original suit.

(6) A further appeal from the appellate decree of a District Judge upon an appeal under sub-section (5), shall lie to the High Court only if the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved."; और

(ग) विद्यमान उप-धारा (3) को उप-धारा (7) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा ।

धारा 171 का संशोधन।

3. धारा 171 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (*xxv*) को (*xxvi*) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित खण्ड से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(*xxv*) any question, as to any land or any right to, or title or interest

in, the land which is an encroached land or in relation to which any person claims that it has vested or is deemed to have vested in him and that he cannot be ejected therefrom under sub-section (1) of section 163; and".

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Bhoo-Rajasva (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (1989 ka Adhiniyam Sankhyank 15) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*]

Act No. 15 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 1989

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD JUNE, 1989)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 1989.

6 of 1954

Amendment of section 163.

2. In section 163 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter called the principal Act),—

(*a*) in clause (*d*) of sub-section (1), for the words "five hundred" and "one thousand", the words "one thousand" and "two thousand" shall, respectively, be substituted ;

(*b*) after sub-section (2), the following sub-sections (3), (4), (5) and (6) shall be added, namely:—

"(3) When there is a question as to title or to the adverse possession, wherein the possession is claimed by an encroacher for a period beyond thirty years in relation to the land from which ejectment is made or is to be made under this section, the Revenue Officer, not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade, shall proceed to determine the question, as if he were a civil court and shall exercise all such powers as are exerciseable by a civil court.

(4) For the determination of the question under sub-section (3), the Revenue Officer shall follow the same procedure as is applicable to the trial of an original suit by a civil court, and he shall record a judgement and decree containing the particulars required by the Code of Civil Procedure, 1908 to be specified therein.

5 of 1908

(5) An appeal from the decree of the Revenue Officer made under sub-section (4) shall lie to the District Judge as if that decree were a decree of a Subordinate Judge in an original suit.

(6) A further appeal from the appellate decree of a District Judge upon an appeal under sub-section (5), shall lie to the High Court only if the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved."; and

(*c*) the existing sub-section (3) shall be renumbered as sub-section (7).

Amendment of section 171

3 The existing clause (*xxv*) of sub-section (2) of section 171 of the principal Act shall be renumbered as (*xxvi*) and before clause so

renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(*xxv*) any question, as to any land or any right to, or title or interest in, the land which is an encroached land or in relation to which any person claims that it has vested or is deemed to have vested in him and that he cannot be ejected therefrom under sub-section (1) of section 163; and".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जून, 1989

क्रमांक एल0एल0आर0 (डी0) (6)-9/89-लैजिस0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 23 जून, 1989 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1989 (1989 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 1989 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम, संख्या 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) क अधीन इसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में सहर्ष प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव ।

1989 का अधिनियम संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1989

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23 जून, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1989 है ।

धारा 11 का संशोधन ।

1987 का 4

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के भाग (अ) की मद संख्या (vi) में आए "कृषि," शब्द और अल्प-विराम के चिह्न के पश्चात् "औद्यानिकी," शब्द और अल्पविराम का चिह्न अन्तः स्थापित किया जाए ।

धारा 12 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में :—

(क) उप-धारा (1) के भाग (अ) की मद संख्या (vii) में आए "कृषि," शब्द और अल्पविराम के चिह्न के पश्चात् "औद्यानिकी," शब्द और अल्प-विराम का चिह्न अन्तःस्थापित किया जाए ।

(ख) उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी : परन्तु यदि बोर्ड की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो उसी कारबार के संव्यवहार क लिए आगामी बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।"

धारा 25 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (6) में आए शब्दों "और तुलनपत्र" का लोप किया जाए ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Krishi, Udyanike Aur Vanikee Vishva-Vidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (1989 ka Adhiniyam Sankhyank 16) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*]

Act No. 16 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) ACT, 1989

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD JUNE, 1989)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 1989.

Amendment of section 11

2. After the word and sign comma "Agriculture," occurring in item (*vi*) of Part (A) of sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter called the principal Act), the word and sign comma "Horticulture," shall be inserted. 4 of 1987

Amendment of section 12

3. In section 12 of the principal Act,—

(*a*) after the word and sign comma "Agriculture," occurring in item (*vii*) of Part (A) of sub-section (1), the word and sign comma "Horticulture," shall be inserted; and

(*b*) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(6) one-third of the members of the Board shall form quorum for a meeting of the Board :

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for the transaction of the same business.".

Amendment of section 25

4. The words "and balance-sheet" occurring in sub-section (6) of section 25 of the principal Act, shall be omitted.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री हि० प्र० शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।